(c) if so, whether this act is in keeping with the well enunciated approach of the Government through the common minimum programme about media autonomy and the right to information; and

(d) if not, whether responsibilities will be fixed for this mistake?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

Quantum of foreign loan on Average Indian

1584. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the per capita foreign loan an Indian owes as on date;

(b) whether Government propose to reduce it substantially;

(c) if so, what steps are proposed in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The per capita foreign debt of the Government works out at Rs. 1601 during 1995-96.

(b) and (c) Government has been following a prudent debt management strategy aimed at reducing the debt service ratio to comfortable levels. This includes measures to promote the growth of exports and other current receipts, reduce the growth of total debt and to encourage non-debt creating inflows such as foreign investment.

(d) Does not arise.

Setting up a Bench of Keraia High Court in Thiruvananthapuram

1585. SHRI THENNALA BALAKRISHNA PILLAI: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether the Central Government have received any proposal from the State Government to start a Bench of Kerala High Court in Thiruvananthapuram; and

(b) if so, what action is taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) No complete proposal has been received from the Government of Kerala, in consultation with the Chief Justice of the Kerala High Court, for establishing a bench of the High Court at Thiruvananthapuram. As such, it is not possible for the Central Government to take any action in the matter.

Freezing of Properties under Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act

1586. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 provides for tracing, freezing and forfeiture of property derived from illicit drug traffic;

(b) if so, whether properties were traced, frozen and forfeited under the Act during the last three years, with year-wise and State-wise detail thereof; and

(c) what steps Government have taken to stop money laundering related to narcotics trafficking in the country, details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANFY AFFAIRS: (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Madam.

(b) As per available information year-wise details regarding frozen and forfeited properties are as follows:

Year	Value of Property Frozen (Rs.)	Value of Property Forfeited (Rs.)
1993	904044.00	NIL
1994	85067571.00	1024400.00
1995	210428345.00	309479.00

State-wise data is not maintained. Tracing of property is an investigative process which may lead to freezing and ultimate forfeiture of property.

(c) Instructions have been issued to all enforcement agencies that special attention should be paid to enforcement of provisions regarding forfeiture of property under the NDPS Act.

राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड योजना, 1980 के अंतर्गत लिया गया सोना

1587. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड योजना, 1980 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के जिन देवताओं/धर्मस्थलों का सोना लिया गया था, उनमें से किस-किस देवता/धर्मस्थल का सोना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज तक लौटाया गया है और किन-किन देवताओं/धर्मस्थलों का मामला अभी तक अधर में लटका है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त मंदिरों के प्रबंधकों के लिए दिल्ली आकर भारतीय रिजर्व बैंक से सोना लेकर वापस जाना संभव नहीं है;

(ग) क्या सरकार उक्त सोने को मंदिर के प्रबंधन को सौंपने हेतु उसे भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से कुल्लू जिला मुख्यालय भिजवाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) कुल्लू जिले के 56 मन्दिरों जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड योजना, 1980 में निवेश किया था जिनमें से 9 मन्दिरों को बांड प्रस्तुत करने पर सोना लौटा दिया गया है और जिन 47 मन्दिरों का सोना अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, उनकी सूची दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से कुल्लू के जिला मुख्यालय को सोना लौटाने के सुझाव पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सहमति नहीं दी है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि जिन बांड धारकों ने 30 ग्राम तक सोना जमा किया है, उन्हें स्वयं दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के कार्यालय में विधिवत, निर्धारित बाण्ड इस अनुरोध के साथ भेज सकते हैं कि उन्हें सोना बीमांकित डाक से भेज दिया जाए। जिन बांड धारकों ने 30 ग्राम से अधिक सोना जमा कराया है वे या तो स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में बांड प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पर बकाया सोना प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय-रक्षा स्वर्ण बाण्ड योजना, 1980 के अन्तर्गत निवेश किए गए स्वर्ण के संबंध में विवरण

क्रम सं०	निवेशक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा सोना (ग्राम में)	वापस किया गया सोना (ग्राम में)
1.	देवता चाऊनाग	2	—
2.	देवता बुझारी कोट	10	—
3.	देवता तरली नाग	2	—
4.	देवता जालन्धरी	18	—